

मंत्रालयों और विभागों की वर्षांत समीक्षा

भाग-1 (पूरक डॉक्यूमेंट: 2024)



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



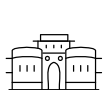
जोधपुर



लखनऊ



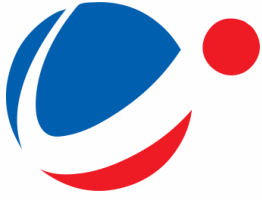
प्रयागराज



पुणे



राँची



मंत्रालयों और विभागों की वर्षात समीक्षा

(भाग-1)

(पूरक डॉक्यूमेंट)

विषय सूची

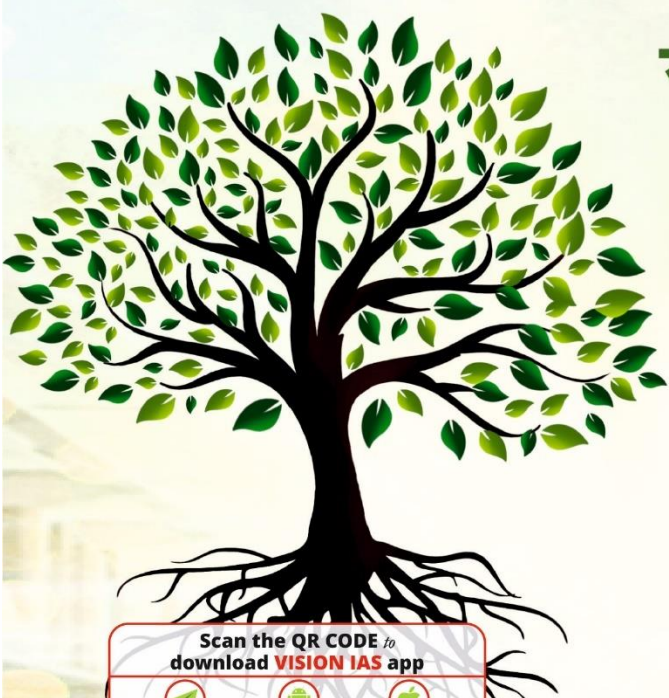
1. कोयला मंत्रालय	2
2. पर्यावरण मंत्रालय	3
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	4
4. रक्षा मंत्रालय	5
5. उपभोक्ता मामले मंत्रालय	7
6. पर्यटन मंत्रालय	8
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय	9
8. रसायन मंत्रालय	10
9. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	11
10. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	12
11. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	12
12. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	14
12.1. मत्स्य पालन विभाग	14
13. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	15
14. जल शक्ति मंत्रालय	17
15. गृह मंत्रालय	18
16. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	20
16.1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	20
16.2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	20
17. इस्पात मंत्रालय	23
18. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	24
18.1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	24
18.2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय)	24
19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	25
20. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	29

नोट: इस डॉक्यूमेंट में वर्ष 2024 के संदर्भ में प्रेस सूचना ब्यूरो पर प्रकाशित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की वर्षात समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा प्रदान किया गया है। इसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों की पहलों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट से UPSC के आगामी इंटरव्यू की तैयारी के लिए तेजी से रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, इसका उपयोग करके अभ्यर्थी अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं।

भाग-1 इसमें भारत सरकार के 20 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षात समीक्षाएं शामिल हैं, जैसा कि विषय-सूची में भी दिया गया है। भारत सरकार के शेष मंत्रालयों/ विभागों की वर्षात समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा भाग-2 में प्रदान किया जाएगा।

1. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)

विषय	प्रमुख पहलें/ प्रगति/ उपलब्धियां
प्रमुख उपलब्धियां	कोयला उत्पादन: वर्ष 2023-24 में देश ने अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादित किया है। कैलेंडर वर्ष 2024 (15 दिसंबर 2024 तक) में देश ने लगभग 963.11 मिलियन टन (अनंतिम) कोयले की आपूर्ति की है। मिशन कोकिंग कोयला: आयात में कमी लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2029-30 तक घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर 140 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यिक खनन: अब तक, कुल 113 कोयला खानों की वाणिज्यिक खनन के तहत सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। कोयला गैसीकरण परियोजना: कोयला गैसीकरण मिशन के तहत, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
सुधार/ नीति	कोयला लिंकेज नीति का क्रियान्वयन: यह नीति गैर-विनियमित क्षेत्र (NRS) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी पर केंद्रित है। कोयले के लिए मूल्य अधिसूचना में संशोधन (कोयला गैसीकरण): कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए NRS लिंकेज नीलामी नीति के तहत सिंथेटिक गैस उत्पादन के लिए एक नया उप-क्षेत्र स्थापित किया गया है। माइन क्लोजर पोर्टल का शुभारंभ: यह पोर्टल खदान बंद होने से जुड़ी गतिविधियों, समय-सीमा और व्यय की निगरानी करता है। नेशनल कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ: यह कोयला खनन में उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है।
सतत विकास	प्रतिपूरक बनीकरण: 4695.65 हेक्टेयर कोयला खनन के लिए उपयोग की गई जमीन को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए चिह्नित किया गया है। इसे भविष्य में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त क्षतिपूरक बनीकरण (ACA) भूमि बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। "एक पेड़ माँ के नाम" पहल: इस पहल का उद्घाटन कोयला क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया।



फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 21 जनवरी, 11 AM | 6 जनवरी, 11 AM

JAIPUR: 20 जनवरी

JODHPUR: 3 दिसंबर

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW

2. पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment)

जलवायु परिवर्तन	जलवायु कार्रवाई और नेट जीरो: भारत जलवायु परिवर्तन का शमन के लिए प्रतिबद्ध है और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): यह कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2025-26 तक कणीय प्रदूषकों (particulate matter) में 40% तक की कमी लाना है। सर्कुलर इकॉनमी और EPR फ्रेमवर्क: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने प्लास्टिक, टायर, बैटरी, उपयोग किए गए तेल और ई-कचरा जैसे क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी (EPR) फ्रेमवर्क लागू किया है। इको-मार्क योजना: MoEFCC ने 1991 की योजना की जगह नए इको-मार्क नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 'LiFE' (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन के भी अनुरूप हैं। ये नियम पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों, संसाधन दक्षता आदि को भी बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP): ICAP का फोकस सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने पर केंद्रित है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंगिबल इनकम्स (MISHTI): यह पहल 5 जून 2024 को शुरू की गई थी। यह मैंग्रोव की पुनर्बहाली और तटीय आवास की संधारणीयता पर केंद्रित है।
वन संरक्षण और प्रबंधन	वन और वन्यजीव प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला: MoEFCC और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल ने 21-22 अगस्त, 2024 को वन और वन्यजीव प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। प्रमुख उपलब्धि: 2023-24 के वनाग्नि मौसम में, 24 घंटे के भीतर बड़ी वनाग्नि को बुझाने की प्रतिशतता पिछले मौसम के 33% से बढ़कर 67% हो गई है।
जैव विविधता	राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP): यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप है। COP-16 में भागीदारी: पर्यावरण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया के कैली में आयोजित जैव विविधता अभिसमय में भाग लिया।
राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB)	नगर वन योजना: राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) ने नगर वन योजना (NVY) को लागू किया है। इसका उद्देश्य 2020-21 से 2026-27 के दौरान देशभर में 600 नगर वनों और 400 नगर वाटिकाओं का विकास करना है। वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, इन शहरी वनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

2025	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 19 जनवरी	2026	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
-------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

प्रमुख उपलब्धियां	वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचकांकों में भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII), 2024 के अनुसार, भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में 39वीं रैंक प्राप्त की है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF): इसे ANRF अधिनियम, 2023 द्वारा स्थापित किया गया है। ANRF अधिनियम, 2023 के प्रावधान 5 फरवरी, 2024 से प्रभावी हुए हैं। इसका उद्देश्य भारत की अनुसंधान और नवाचार क्षमता को मजबूत करना और इसे वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन: इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रेरित, पोषित और बढ़ावा देना है। साथ ही, क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और नवोन्मेषी इकोसिस्टम निर्मित करना है। नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए अग्रणी भू-स्थानिक डेटा, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी: राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के अनुरूप भू-स्थानिक क्षमता निर्माण उप-योजना के तहत देशभर के स्कूलों में 'स्पैटियल थिंकिंग प्रोग्राम' की शुरुआत की गई। इसमें 7 राज्य (गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान) को कवर किया गया है। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM): यह मिशन MeitY और DST ने संयुक्त रूप से लागू किया है। इसके तहत 2023 तक पूरे देश में 28 स्थानों पर 27 पेटाफ्लॉप्स (PF) की कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण किया गया है।
CSIR की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां	स्वदेशी सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी "रेजुपवे (REJUPAVE)": यह प्रौद्योगिकी CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिटुमिनस सड़कों का निर्माण करना है, जो निम्न और शून्य से नीचे के तापमान पर काम कर सके। - NH-66 मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैंग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया। - CSIR-NIO, गोवा ने प्रवाल भित्तियों की निगरानी के लिए सी-बॉट नामक एक अंडरवाटर वाहन लॉन्च किया है। - भारत की पहली लिथियम बैटरी रीसाइक्लिंग पायलट सुविधा का उद्घाटन किया गया। अधिक-ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह (हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट) का सफल परीक्षण किया गया। CL-20 ईंधन विकसित किया गया है। CL-20 RDX और HMX जैसे पारंपरिक प्रणोदकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। इसमें हाई एनर्जी रिलीज और बेहतर ऑक्सीडाइजर-टू-फ्यूल अनुपात की क्षमता है। यह रॉकेट्स और मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण है। - CSIR-CCMB ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए चीरफाड़ रहित (नॉन इनवेसिव) रक्त परीक्षण विकसित किया। - CSIR-NAL ने भारत की रक्षा के लिए स्वदेशी कामिकेज़ ड्रोन का अनावरण किया। - CSIR-NCL और CeNS ने ऊर्जा संचयन के लिए नया पीजोइलेक्ट्रिक नैनोकंपोजिट विकसित किया। - CSIR-CRRI तकनीक का उपयोग करके बायो-बिटुमिन सतह वाला एशिया का पहला राजमार्ग तैयार किया गया है। - CSIR-NEIST ने अरुणाचल प्रदेश में एक नए फूल वाले पौधे की प्रजाति "बेगोनिया नरहरि" की खोज की है। इसका नाम संस्था के पूर्व निदेशक 'नरहरि' के सम्मान में रखा गया है।
नई पहल	जलवायु जोखिम मूल्यांकन अध्ययन: IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके जिला-स्तरीय बाढ़ और सूखे के जोखिमों पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खतरा, जोखिम, सुभेद्यता और जोखिम मानचित्र तैयार किए गए। ग्लेशियोलॉजी (हिमनद विज्ञान) में 21-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम: देशभर के बीस डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेल छात्रों के लिए ट्रास, लद्दाख में माचोई ग्लेशियर में ऑन-फील्ड प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं (WISE) - शोध के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी (KIRAN): दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पहली, महिला अंतर्राष्ट्रीय अनुदान सहायता (WINGS/ विंग्स) कार्यक्रम भारतीय महिला वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी, महिला नेतृत्व कार्यक्रम जो प्रारंभिक और मध्य-स्तरीय महिला वैज्ञानिकों के लिए है, जो उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करने में मदद करती है।

4. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

रक्षा में आत्मनिर्भरता	सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची: रक्षा उत्पादन विभाग ने पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL) जारी की है। इसमें महत्वपूर्ण घटकों और सामग्रियों सहित 346 वस्तुएं शामिल हैं। - यह पिछली चार PIL में शामिल 4,666 वस्तुओं के अतिरिक्त है। रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन: भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल उत्पादन में से लगभग 79.2 प्रतिशत का योगदान DPSU/ PSU का और 20.8 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का है। रिकॉर्ड रक्षा निर्यात: वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात बढ़कर 21,083 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 31 गुना अधिक है। - इसमें निजी क्षेत्र का योगदान 60% था, जबकि DPSU का योगदान 40% था। C-295 टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स: अक्टूबर 2024 में गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, जहां C-295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाए जाएंगे। भारत में निर्मित पहला C-295 2026 में तैयार होगा, और बाकी विमानों की आपूर्ति 2031 तक की जाएगी। इंडियन लाइट टैंक 'ज़ोरावर': DRDO द्वारा विकसित और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित ज़ोरावर ने उच्च-ऊँचाई (4200 मीटर) और रेगिस्तानी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है।
प्रमुख अधिग्रहण	- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) और रक्षा खरीद बोर्ड (DPB) ने 2024 के दौरान 4,22,129.55 करोड़ रुपये की राशि के 40 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। - इनमें से 94.19 प्रतिशत स्वदेशी स्रोतों के लिए खरीदे जाएंगे।
मुख्य प्रवेश/कमीशनिंग	INS अरिघाट: दूसरी अरिहंत-श्रेणी की पनडुब्बी 'INS अरिघाट' को 29 अगस्त, 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। INS तुशील: INS तुशील (F 70), नवीनतम मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को 09 दिसंबर, 2024 को रूस के कलनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। LCH प्रचंड: सभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LSP की प्रक्रिया फरवरी, 2024 में पूरी हुई है।
भारतीय सेना	अवसंरचना: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारतीय सेना, BRO और अन्य एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सड़कें, सैनिकों के आवास और विमानन सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 2028 तक BRO की 27,000 किलोमीटर की 470 सड़कें बनाने की योजना है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल: जल प्रहार-I, ऑपरेशन सी टेस्ट और पोखरण में एक लाइव प्रदर्शन जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का प्रदर्शन किया गया। नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम: आर्मी डिजाइन ब्यूरो (ADB) 'मेक प्रोजेक्ट्स', iDEX और PIL जैसी पहलों के माध्यम से स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देता है। अनुसंधान एवं विकास, प्रोटोटाइप विकास और उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है। सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए प्रमुख नवाचार और आकाशतीर जैसी परियोजनाएं भारत की रक्षा प्रणाली और संचालन क्षमताओं को मजबूत कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला अधिकारी: वर्तमान में विभिन्न मिशनों में स्टाफ अधिकारियों/ सैन्य पर्यवेक्षकों के 23% पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अनुरूप है।
भारतीय नौसेना	- समुद्री डकैती-रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों ने लोगों की जान बचाने, व्यापारिक जहाजों की रक्षा करने और समुद्री डकैती तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। - महत्वपूर्ण आयोजनों में अभ्यास 'मिलन' 2024 महत्वपूर्ण है जिसमें 47 देशों ने भाग लिया। - भारतीय नौसेना ने सभी शाखाओं में महिलाओं को भर्ती करके लैंगिक तटस्थता को अपनाया है। उदाहरण: वर्तमान में, 1,321 महिला अग्निवीर सेवा में हैं।

भारतीय वायुसेना	- भारतीय वायुसेना (IAF) स्पेन, आर्मेनिया और आइवरी कोस्ट में छह नए रक्षा विंग स्थापित कर रही है। इस प्रकार वायुसेना वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही है। 2024 के प्रमुख अभ्यासों में डेजर्ट नाइट, पिच ब्लैक और गगन शक्ति अभ्यास शामिल हैं। इन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। - सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने लक्षद्वीप में हवाई क्षेत्र के निर्माण और विस्तार तथा न्योमा और डीसा में अवसंरचना विकास के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। - RDP-2024 में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना 48 अग्निवीर वायु महिलाएं शामिल थीं। - पोखरण रेंज में अभ्यास वायुशक्ति-24 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना दुश्मन पर किस तरह से प्रहार करने में सक्षम है। - अभ्यास गगन शक्ति-24 में तीनों सेनाओं ने सभी डोमेन में एक समग्र युद्ध संचालन का अभ्यास किया। इस अभ्यास में आकस्मिक योजनाएं बनाई गईं तथा उनके लिए टेबलटॉप वॉर-गेम आयोजित किए गए। - वॉर-गेम एक रणनीति गेम है जिसमें दो या दो से अधिक भागीदार सशस्त्र संघर्ष के अनुकरण में विरोधी सशस्त्र बलों की कमान संभालते हैं।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG)	- ICG ने जनवरी 2024 में ICG जहाजों और प्रतिष्ठानों के लिए सॉफ्टवेयर डिफाईंड रेडियो की आपूर्ति हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। - गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी डिज़ाइन किए गए दो प्रदूषण नियंत्रण पोतों का निर्माण कर रहा है। पहला पोत अगस्त 2024 में जलावतरण किया गया। इसका नाम 'समुद्र प्रताप' है। - अगस्त 2024 में, रक्षा मंत्री ने चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। - जुलाई 2024 में, ICG ने केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी गांव में भूस्खलन के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन 'ऑप सहायता 02/24' शुरू किया।
राष्ट्रीय कैडेट कोर	सरकार ने तीन लाख कैडेट विस्तार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत NCC की कुल संख्या को बढ़ाकर 20 लाख कैडेट्स करने की योजना है। इसमें लगभग 40% महिला कैडेट्स होंगी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	- ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से नई पीढ़ी की आकाश (AKASH-NG) मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। - DRDO ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) - अभ्यास के चार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। - बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। - VSHORADS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। - मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक का उपयोग करके स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया।
सीमा सड़क संगठन	- सेला सुरंग का उद्घाटन: यह सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। - शिकुन ला सुरंग का उद्घाटन: इस परियोजना में लेह को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदुम-दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाना है। - मुध-न्योमा एयरफील्ड: न्योमा-मुध एयरफील्ड परियोजना (2.7 किमी) वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से 46 कि.मी. की दूरी पर 13700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर बेस में से एक होगी।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2025: **19 JANUARY**
हिन्दी माध्यम 2025: **19 जनवरी**

5. उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs)

मूल्य निगरानी	- मूल्य निगरानी प्रभाग (PMD) 1998 में स्थापित किया गया था। यह 38 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य की दैनिक आधार पर निगरानी करता है। - यह मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund) का भी प्रबंधन करता है। - लेहू और कारगिल में नए केंद्रों की स्थापना के साथ लद्दाख को भी मूल्य निगरानी नेटवर्क में शामिल किया गया। इससे इसका कवरेज बढ़कर 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक हो गया है।
मूल्य स्थिरीकरण	- मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) की स्थापना 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ की गई थी, ताकि कृषि-बागवानी वस्तुओं, जैसे- प्याज, आलू और दालों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके। - PSF को अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के PM-AASHA योजना में एकीकृत कर दिया गया है। - चना, मूंग और मसूर के स्टॉक्स की खुदरा बिक्री "भारत दाल" ब्रांड के तहत की जा रही है।
ई-फाइलिंग	- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत "edaakhil.nic.in" नामक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है। इसके तहत उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। - हाल ही में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ई-दाखिल की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, अब यह पोर्टल देश भर में NCDRC और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है।
ई-जागृति का शुभारंभ	उपभोक्ताओं की सुविधा और उनके दरवाजे तक न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है।
लीगल मेट्रोलाजी	- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और राज्य विधिक मेट्रोलाजी विभागों के साथ एक नेशनल लीगल मेट्रोलाजी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। - लीगल मेट्रोलाजी के अंतर्गत सभी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके तहत व्यवसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और अनुपालन के बोझ को कम किया गया है। - अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन (OIML): भारत ने कानूनी माप विज्ञान में OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने वाला 13वां देश बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह भारत को वैश्विक मानदंडों के समकक्ष लाता है।
उपभोक्ता कल्याण कोष	- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष बनाने के लिए 75:25 के आधार पर (विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10) एकमुश्त अनुदान के रूप में आरंभिक राशि प्राप्त होती है। - वर्तमान स्थिति: 25 राज्यों ने उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना की है।
मानक विकास में नई पहल	- मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP) 2022-27: इसने देश में मानकीकरण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 रणनीतिक आवश्यकताओं की पहचान की है। - प्रमुख तकनीकी संस्थानों में BIS मानकीकरण चेयर का निर्माण करना।

DAKSHA MAINS
 MENTORING PROGRAM 2024

दिनांक
13 जनवरी

अवधि
3 महीने

हिन्दी/English माध्यम

दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम

(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)

For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066

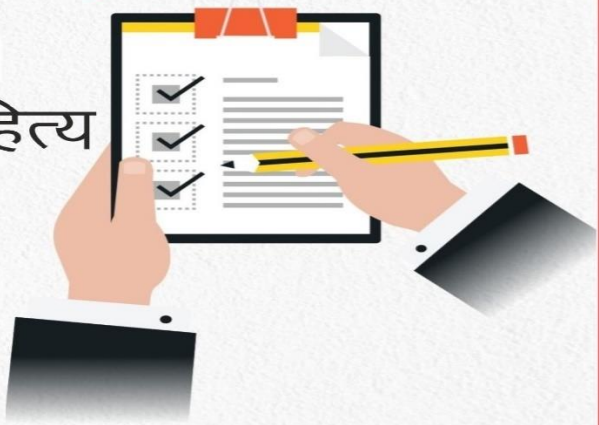
6. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

अवसंरचना	- पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 75 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। - पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (SD2.0) के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार संधारणीय और जिम्मेदार स्थलों का विकास करना है। - SD2.0 के तहत 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। - पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद (PRASHAD) योजना के तहत कुल 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 23 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
चुनौती आधारित गंतव्य विकास	- पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप-योजना के रूप में 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। - इस योजना के तहत, चार विषयगत श्रेणियों (i) आध्यात्मिक पर्यटन, (ii) संस्कृति और विरासत, (iii) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, (iv) ईकोटूरिज्म और अमृत धरोहर स्थलों के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
प्रचार और मार्केटिंग	- पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले में "भारत पर्व" कार्यक्रम का आयोजन किया। - देश के विविध पर्यटन आकर्षणों को प्रदर्शित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के थीम आधारित पवेलियन स्थापित किए गए। 'देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024': यह एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। - भारतीय डायस्पोरा सदस्यों को अतुल्य भारत के राजदूत के रूप में तैयार करने के लिए 'चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान' शुरू किया गया है।
पर्यटन सांख्यिकी	2023 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (ITAs) 18.89 मिलियन था। 2023 के दौरान भारत में घरेलू पर्यटक यात्राएं (DTV) 2509 मिलियन थीं।
सतत विकास	पर्यटन मंत्रालय ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उन गांवों को मान्यता देना है जो पर्यटन स्थलों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभ: 19 जनवरी



7. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region)

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं	- कुल स्वीकृत परियोजनाएं: 1970.54 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाएं। - कवर की गई योजनाएं: - NESIDS-OTRI: पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़कों के अलावा)। - NESIDS- सड़कें: पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़कें)। - PM-डिवाइन (PM-DevINE): पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। - पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की योजनाएं। - विशेष विकास पैकेज।
डिजिटलीकरण हेतु पहलें	- योजनाओं के लिए सरल दिशा-निर्देश: PM-डिवाइन, NESIDS (OTRI), NESIDS (सड़कों) के लिए दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित किया गया है, ताकि संयुक्त रूप से अवधारणा नोट्स (Concept Note) पर विचार किया जा सके। इससे परियोजना की संकल्पना और अनुमोदन में लगने वाले समय में कमी आएगी। - वित्तीय एवं क्षेत्रीय सीमांकन को तर्कसंगत बनाना: परियोजनाओं की मंजूरी के दोहराव को रोकने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं के बीच वित्तीय एवं क्षेत्रीय सीमांकन को तर्कसंगत बनाया गया है। - पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल: यह अवधारणा नोट्स की प्रस्तुति और ट्रैकिंग को डिजिटल बनाता है। - पीएम गति शक्ति पोर्टल: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) के संस्करण के तहत चालू और पूर्ण परियोजनाओं के जियो टैग किए गए विवरणों को ट्रैक करता है।
कार्यबलों का गठन करना	- अगरवुड कार्य बल: अगर दुनिया के सबसे मूल्यवान वृक्षों में से एक है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) का एक देशज वृक्ष है, इसका उपयोग दवाओं और सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। - पर्यटन कार्य बल: प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करना।
महत्वपूर्ण पहलें	- पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम: इसमें उत्तर-पूर्व सम्मेलन, विविधता का अमृत महोत्सव, अष्टलक्ष्मी महोत्सव आदि शामिल हैं। - नीति और विकास संवाद: पूर्वोत्तर विकास चिंतन शिविर (सितंबर 2024) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए 54 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है। - सतत कृषि को बढ़ावा देना: वर्ल्ड फूड इंडिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका के लिए सतत कृषि के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। - आर्थिक और वित्तीय पहल: बैंकर्स कॉन्क्लेव में वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पांच सूत्रीय फ्रेमवर्क	- प्रतिस्पर्धात्मक मैट्रिक्स और SWOT विश्लेषण: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने पूर्वोत्तर राज्यों की एक-दूसरे के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन किया है। - वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: इसका उद्देश्य उन्नत अवसंरचना प्रदान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम) का विकास करना है। - पूंजी निवेश रणनीति: MDoNER द्वारा संचालित योजनाओं के तहत प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 100% परिपूर्णता का दृष्टिकोण: MDoNER का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में शुरू की गई पहलों को अधिक प्रभावशाली रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख विचार को लागू करना और पूर्णता प्राप्त करना है। - प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: जो राज्य परियोजनाओं को अधिक दक्षता के साथ पूरा करने और उन्हें संचालित करने में सक्षम होंगे, उन्हें अधिक बजट आवंटित किया जाएगा।

8. रसायन मंत्रालय (Ministry of Chemicals)

पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना/ पहलें	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग पेट्रो रसायन की नई योजना को निम्नलिखित उप-योजनाओं के साथ क्रियान्वित करता है: (i) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना; (ii) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की योजना; और (iii) पेट्रो रसायन रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन योजना।
केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)	- यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी उच्चतर शिक्षा संस्थान है। - CIPET की प्रमुख गतिविधियां/ उपलब्धियां: शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम: यह पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में NSQF-केंद्रित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (NSQC) द्वारा अनुमोदित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (SDTP) आयोजित करता है। प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं: प्लास्टिक प्रसंस्करण, डिजाइन और टूलिंग के क्षेत्र में 59,756 प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान की गई हैं। - CIPET ने पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल के रूप में सुव्यवस्थित अनुसंधान एवं विकास विंग स्थापित की है।
विभागों/ अन्य संस्थानों की अन्य उपलब्धियां	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने CPDS योजना के तहत "इंडिया केम 2024" के 13वें संस्करण की सबसे बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया।



"You are as strong as your Foundation"

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS

2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app





DELHI: | 10 JAN, 9 AM | 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 21 जनवरी, 11 AM | 6 जनवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN

BENGALURU: 18 FEB

BHOPAL: 5 DEC

HYDERABAD: 9 DEC

JAIPUR: 20 JAN

JODHPUR: 3 DEC

LUCKNOW: 11 FEB

PUNE: 20 JAN

ADMISSION OPEN

CHANDIGARH

9. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs)

मुख्य अपडेट	• स्मार्ट सिटी मिशन ○ सभी 100 स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC), सहित ○ 84,000 CCTV निगरानी कैमरे, 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स, 3,000 से अधिक सार्वजनिक संबोधन प्रणालियां स्थापित की गई। • स्वच्छ भारत मिशन ○ वित्तीय अपडेट: सरकार ने 9 राज्यों में परियोजनाओं के लिए 1,123 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। ○ प्रमुख अवसंरचना विकास के बारे में अपडेट: गुजरात के अहमदाबाद के पिपलाज में 375 करोड़ रुपये की लागत से 15 मेगावाट क्षमता वाले 1000 मीट्रिक टन के अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया। ○ पुराने कचरे के प्रबंधन के बारे में अपडेट: अहमदाबाद और हैदराबाद में कई सालों से जमा कचरे के दो विशाल ढेर का निपटारा किया गया। ○ 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम: एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के सहयोग से 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट निपटारा परियोजनाएं चल रही हैं। • अमृत और अमृत मिशन 2.0: इसके तहत प्रतिदिन 4,649 MLD जल उपचार क्षमता और प्रतिदिन 4,429 MLD सीवेज उपचार क्षमता निर्मित की गई। • DAY-NULM के मुख्य अपडेट: ○ 1 करोड़ से अधिक शहरी गरीब महिलाओं को 9.96 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया गया है। ○ कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से 39.39 लाख से अधिक आजीविकाएं सृजित की गई हैं।
अन्य मुख्य उपलब्धियां	• शहरी गतिशीलता और संधारणीयता से जुड़ी पहलें ○ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का विस्तार: इस खंड का 42 किलोमीटर हिस्सा संचालित किया जा चुका है। ○ 16 अगस्त 2023 को आरंभ की गई "PM-ई-बस सेवा" का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शहरी बस संचालन सुविधा बढ़ाना है। • प्रधान मंत्री आवास योजना (2.0): प्रवासी आबादी/ कामकाजी महिलाओं/ औद्योगिक श्रमिकों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए एक नया रेंटल हाउसिंग वर्टिकल पेश किया गया है।



ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रेहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट		
5 फंडामेंटल टेस्ट	15 एप्लाइड टेस्ट	
10 फुल लेंथ टेस्ट		



2025	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 19 जनवरी	2026	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
-------------	--	---	-------------	--	--

10. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)

अभूतपूर्व उपलब्धियां	- पेरिस ओलंपिक: 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ शानदार उपलब्धि। 2024 पेरिस पैरालंपिक खेल (अब तक का सबसे बड़ा दल): 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया। - शतरंज में अभूतपूर्व उपलब्धियां: - हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड: भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। - डी. गुक्ते ने 2024 में सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
प्रमुख पहलें	- अस्मिता/ ASMITA महिला लीग के साथ महिला खेलों को बढ़ावा देना: अस्मिता (कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित कर खेल उपलब्धियां हासिल करना) महिला लीग पूरे देश में 20 खेल विधाओं में आयोजित की गई है। - कीर्ति (KIRTI) (खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन) कार्यक्रम: 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करना। इसके लिए देश भर में 1.8 लाख से अधिक दक्षता परीक्षण आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम ने एक निर्बाध और कुशल प्रतिभा पहचान प्रणाली सुनिश्चित की है। - रीसेट/ RESET (पूर्व खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण) कार्यक्रम: 29 अगस्त 2024 को पूर्व खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

11. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME)

प्रमुख पहलें और उपलब्धियां	- पीएम विश्वकर्मा (PM VISHWAKARMA): - पंजीकरण: इस योजना के तहत लगभग 25 लाख आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। - यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। - MSMEs का औपचारिकरण - उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता मंच (UAP) पर 5.70 करोड़ MSMEs पंजीकृत हैं। - क्रेडिट गारंटी योजना - यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्रदान करने की एक फ्लैगशिप योजना है। 'MSME - व्यापार सक्षमता और विपणन (MSME-TEAM)' योजना - इसका लक्ष्य 'MSMEs के बीच व्यापार और वाणिज्य के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, 5 लाख MSMEs को डिजिटलीकरण में प्रशिक्षित और सशक्त किया जाएगा, जिनमें से 2.5 लाख MSEs महिला उद्यमी होंगी। - प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्द्धन केंद्र (CREATE) - लेह में स्थापित यह केंद्र पशुमिना ऊन बनाने, गुलाब और अन्य फूलों से तेल निकालने के लिए उत्पादन सुविधा के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
अन्य योजनाएं/ पहलें	- क्रेडिट तक पहुंच - प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (2008) - आत्मनिर्भर भारत निधि योजना (2021): इसके तहत उन MSMEs को इक्विटी फंडिंग प्रदान की जाती है, जिनमें आर्थिक तरक्की करने और बड़ी इकाइयां बनने की क्षमता व व्यवहार्यता है। - खरीद और विपणन सहायता - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति: सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ CPSEs को अपनी वार्षिक खरीद का कम-से-कम 25% MSEs से खरीदना अनिवार्य है। इसमें से: - SC/ ST के स्वामित्व वाले MSEs से 4%, और

	▪ महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSEs से 3% खरीदना शामिल हैं। • प्रौद्योगिकी तक पहुंच ○ MSME चैंपियंस योजना: इस योजना के तीन घटक हैं: ▪ 'MSME-सस्टेनेबल' (ZED), ▪ 'MSME-प्रतिस्पर्धी' (LEAN) और ▪ 'MSME-इनोवेटिव' (इनक्यूबेशन, डिजाइन, IPR)। ○ प्रौद्योगिकी केंद्र (जिन्हें टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के नाम से भी जाना जाता है)। • SC/STs और NER में MSMEs को बढ़ावा देना ○ राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH): इस योजना का उद्देश्य SC/ ST के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और CPSEs द्वारा निर्धारित 4% सार्वजनिक खरीद के प्रावधान का पालन करना है। ○ NER और सिक्किम में MSMEs को बढ़ावा देने की योजना: इसका उद्देश्य NER में स्थित MSMEs के लिए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण अथवा उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। • MSME प्रदर्शन कार्यक्रम (RAMP) योजना ○ यह विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य MSMEs की बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है। • खादी, ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा ○ खादी और ग्रामोद्योग ▪ यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। ▪ प्रमुख घटक: खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना।
NSIC और MGIRI की उपलब्धियां	• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) ○ यह MSMEs को कच्चे माल की खरीद के लिए क्रेडिट सहायता प्रदान करता है। MSMEs के लिए NSIC बैंक गारंटी जारी की जाती है, जिससे वे कच्चे माल के लिए भुगतान में देरी के बावजूद सप्लायर से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। • महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (MGIRI) ○ यह एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है, जो ग्रामीण समुदायों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
शिकायत निवारण पोर्टल	• इसके लिए एक चैंपियंस पोर्टल (CHAMPIONS portal) लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं सहित शिकायत निवारण और MSMEs का समर्थन शामिल है।

फास्ट ट्रेक कोर्स 2025

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- PT 365 की कक्षाएं
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

कला एवं संस्कृति

राज्यवस्था

अंतराष्ट्रीय संबंध

पर्यावरण

भूगोल

भारत का इतिहास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अर्थव्यवस्था

प्रवेश प्रारंभ

Available in English & हिन्दी

Live/Online

Classes available

12. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)

12.1. मत्स्य पालन विभाग (Department of Fisheries)

सीवीड (समुद्री शैवाल) एवं मोती और सजावटी मत्स्य पालन	- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का लक्ष्य 2025 तक देश के सीवीड उत्पादन को 1.12 मिलियन टन से अधिक बढ़ाना है। - विभाग द्वारा हजारीबाग में मोती की खेती, मदुरै में सजावटी मत्स्य पालन और लक्षद्वीप में सीवीड क्लस्टर स्थापित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है।
मत्स्य पालन स्टार्ट-अप्स और मत्स्य पालन किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की सहायता के लिए	कम-से-कम 100 मत्स्य स्टार्ट-अप्स, सहकारी समितियों, FPOs और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देने के लिए 3 इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है।
पहलें और परियोजनाएं	- NFDP (राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम) पोर्टल: यह मत्स्य पालन से जुड़े हितधारकों के पंजीकरण, जानकारी साझा करने, सेवाओं और मत्स्य पालन से संबंधित सहायता के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। - NFDP को प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के तहत स्थापित किया गया है। - सरकार ने 100 तटीय गांवों को संधारणीय मत्स्यन प्रथाओं सहित जलवायु लचीले गांवों के रूप में विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। - PMMSY के तहत पांच एकीकृत एक्वा पार्कों (IAPs) को मंजूरी दी गई है। - रंगीन मछली मोबाइल ऐप: यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्रक की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। - अन्य पहलें: - डेटा-संचालित नीति निर्धारण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना का शुभारंभ किया गया है। - शार्क संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई है। अवैध मत्स्यन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ संयुक्त क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की गई है। - समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने हेतु ग्लोलिटर (GloLitter) पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए IMO-FAO के साथ साझेदारी की गई है।
प्रमुख योजनाएं	- नीली क्रांति योजना: यह मत्स्य पालन क्षेत्रक के एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। - मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष: यह कोष नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और अनुसूचित बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। - किसान क्रेडिट कार्ड: सरकार ने 2018-19 के दौरान मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए KCC सुविधा का विस्तार किया है।



UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए
रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु
7 माह का कार्यक्रम)

WWW.VISIONIAS.IN
 8468022022

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटoring प्रोग्राम 2025

6 जनवरी 2025

13. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

हरित जलमार्ग पहल	- इस पहल का शुभारंभ वाराणसी में किया गया है। इसके तहत दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। - अयोध्या में सरयू नदी और वाराणसी में गंगा नदी पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों का संचालन किया जा रहा है।
भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-UAE के बीच उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान एक अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते का उद्देश्य बंदरगाहों, समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट	- भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक बड़ी छलांग है क्योंकि 2014 में भारत 44वें स्थान पर था। - भारतीय बंदरगाहों का "टर्न अराउंड टाइम" 0.9 दिन तक पहुंच गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन), सिंगापुर (1.0 दिन) आदि से बेहतर है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद	भारत 2024-25 की दो साल की अवधि के लिए IMO परिषद में पुनर्निर्वाचित हुआ है।
कूज भारत मिशन	- इस मिशन का उद्देश्य देश में कूज पर्यटन की जबरदस्त संभावनाओं को बढ़ावा देना है। - इस मिशन के तहत पाँच वर्षों के भीतर यानी 2029 तक कूज यात्री यातायात को दोगुना करके देश के कूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)	- इसे गुजरात के लोथल में स्थापित किया गया है। - यह एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास, विरासत, और समुद्री शक्ति के रूप में इसकी रणनीतिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। - लोथल, हड़प्पा सभ्यता का एक संपन्न बंदरगाह था।
गैलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP)	- गैलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास किया गया है। - इस पोर्ट के माध्यम से भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश और म्यांमार के बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को आकर्षित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय कार्गो हैंडलिंग क्षमता को भी बढ़ाएगा।
वधावन बंदरगाह	महाराष्ट्र में दहानू के पास वधावन में महापत्तन का शिलान्यास किया गया है।
सागर आकलन दिशा-निर्देश	"सागर आकलन" दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन का मानकीकरण करना और उसमें सुधार करना है।
शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल, चाबहार	- इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल, चाबहार के विकास के लिए एक दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। - चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत-ईरान के बीच एक प्रमुख साझा व्यापारिक प्रयास है। यह परियोजना INSTC को मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)	समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप पारंपरिक ईंधन-आधारित हार्बर टग्स को ग्रीन टग्स से बदलने का प्रस्ताव है।
शिपिंग	- VOC पोर्ट, तूतीकोरिन से MV MSS गैलेना को हरी झंडी दिखाकर भारत-मालदीव शिपिंग सेवा की शुरुआत की गई है। - अंतर्राष्ट्रीय यात्री नौका सेवा की शुरुआत (भारत और श्रीलंका): नागपट्टिनम (भारत) और कांकेसथुराई (श्रीलंका) के बीच नौका सेवा की फिर से शुरुआत की गई है।

	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत IFSC लिमिटेड: SCI ने गिफ्ट सिटी में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है।
अंतर्देशीय जलमार्ग	- कार्गो प्रमोशन योजना - कार्गो प्रमोशन योजना का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। - यह योजना कार्गो मालिकों को 35% प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि वे भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) के तहत NW-1, NW-2, और NW-16 पर कार्गो आवाजाही को बढ़ाएं। - कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की पहली बैठक आयोजित की गई थी। 2047 तक 100% हरित जहाजों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'हरित नौका'- अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित संक्रमण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 'रिवर क्रूज पर्यटन रोडमैप, 2047' का शुभारंभ किया गया है। - वाराणसी में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत तैनात किया गया है।
लाइटहाउस और जहाज	अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर रानी लक्ष्मीबाई शिला (मध्य समुद्र) पर लाइट हाउस टॉवर की स्थापना की गई।



विषय रिवीजन क्लासेस GS प्रीलिम्स

UPSC CSE 2025

11 फरवरी, दोपहर 1 बजे

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध



14. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

योजनाएं	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) - केंद्र प्रायोजित योजना। - दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 में ओडीएफ प्लस गांवों में 460% की उल्लेखनीय वृद्धि। गोबरधन (GOBARdhan) SBM-G चरण II की महत्वपूर्ण पहल है: इसके तहत 990 से अधिक सामुदायिक/क्लस्टर स्तर के बायोगैस संयंत्र कार्य कर रहे हैं। लाइट हाउस पहल: यह पहल इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन- फिक्की (ISC- FICCI) के सहयोग से 209 गांवों को मॉडल ओडीएफ प्लस गांवों के रूप में विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। जल जीवन मिशन (2019) 15.30 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करना। नल से पेयजल का कवरेज - आकांक्षी जिले- सरकार द्वारा पहचाने गए 112 आकांक्षी जिलों में से 15 जिलों ने 100% नल से जल कवरेज प्राप्त कर लिया है। सिटीजन कॉर्नर- गांव में जल की गुणवत्ता और आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम - SBMG और JJM: यह ऐसा मंच है जहां विकास के साझेदार और क्षेत्रीय साझेदार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक साथ आ सकते हैं। PM गति-शक्ति: जल जीवन मिशन की रणनीति का प्रमुख पहलू पीएम गति-शक्ति पोर्टल के साथ इसके बुनियादी ढांचे के डेटा का एकीकरण करना है।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR)	पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए SGLR प्रणाली को लागू किया है। - इसका लक्ष्य स्वच्छता प्रौद्योगिकियों में सुधार और उच्च स्वच्छता ग्रीन रेटिंग हासिल करना है।
नल जल मित्र कार्यक्रम (NJMP)	गांवों में कार्यरत राजमिस्त्री, मैकेनिक और प्लम्बर जैसे स्थानीय व्यक्तियों को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें "नल जल मित्र" के रूप में तैयार करना।
नल जल सेवा पोर्टल	इस पोर्टल का लक्ष्य ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर उपयोग के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस और राज्य स्तर के प्रशासकों के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड शामिल हैं।
इनोवेशन चैलेंज	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर इसे शुरू किया है। - इसका उद्देश्य स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान खोजना है।
अन्य	श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान को WASH (SBM और JJM) के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। - सतत विकास लक्ष्य-6 पर फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय WASH (वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन) सम्मेलन आयोजित किया गया।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

2025	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 19 जनवरी	2026	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
-------------	--	---	-------------	--	--

15. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

नए ऐतिहासिक कानूनों के द्वारा नागरिकों का सशक्तीकरण	- तीन नए आपराधिक कानून- - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए। - इन कानूनों का निर्वाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च की गई। - नागरिकता संशोधन अधिनियम: ये नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए।
जम्मू और कश्मीर के लिए सामाजिक समानता	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024: यह पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया एक ऐतिहासिक विधेयक है।
वामपंथी उग्रवाद	- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली हिंसा के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पिछले 4 दशकों में पहली बार 100 से नीचे आ गई है। 31 मार्च, 2026 से पहले वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। - बस्तर ओलंपिक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित हुआ। - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक-एक गाय या भैंस देकर डेयरी को-ऑपरेटिव शुरू किया जा रहा है। - छत्तीसगढ़ सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मसमर्पण नीति बनाई है, जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: नार्को-टेरर नेक्सस को तोड़ना	- राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' लॉन्च किया गया। - केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में संपूर्ण-सरकार अप्रोच तथा संरचनात्मक, संस्थागत और सूचनात्मक सुधारों के तीन स्तंभों के आधार पर इस लड़ाई से लड़ने की कोशिश की है।
आपदाओं में जीरो कैजुअल्टी	- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक: अधिक प्रभावी तरीके से और तीव्रता के साथ आपदाओं से निपटने के लिए मोचन बलों को सशक्त बनाया जा रहा है। - छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 'राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' को मंजूरी दी गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र	'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट' का मंत्र अपनाया गया है। - केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (The Indigenous Progressive Regional Alliance: TIPRA) और अन्य हितधारकों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। - देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनसंख्या की मूल संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को खत्म करने का फैसला किया गया।
आतंक मुक्त भारत	- हिज्ब-उत-तहरीर को UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया। 9 संगठनों को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया। - गोल्डी बरार और कासिम गुज्जर को आतंकवादी घोषित किया गया। - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का 'डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS)' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
डिजिटल डिफेंस और फॉरेंसिक एक्सपर्टीज का सशक्तीकरण	- कैबिनेट ने केंद्रीय योजना "नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम" (N.F.I.E.S) को मंजूरी दी। - साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी क्षेत्र दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने हेतु समन्वय बढ़ाना है। - समन्वय (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) एक प्रकार का डेटा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। यह डेटा साझाकरण और विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

	- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) में 5,000 'साइबर कमांडो' की एक सेना स्थापित की जाएगी। - नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' बनाई जा रही है।
महिला सशक्तीकरण: सुरक्षा, सम्मान और गरिमा	- CISF में केवल महिला कर्मियों से युक्त पहली बटालियन की स्थापना की गई। 'महिलाओं की सुरक्षा' से जुड़ी अम्ब्रेला योजना के क्रियान्वयन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
सुरक्षित सीमाएं, सुरक्षित भारत	पश्चिम बंगाल के पेद्रापोल में यात्री-टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण पहलें	- लद्दाख: 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग की स्थापना की गई। - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर "श्री विजय पुरम" किया गया। - दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर 'फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम' का उद्घाटन किया गया। - नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।



पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

प्रवेश प्रारंभ

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री-DAF सेशन: यह DAF में मरे जाने वाले एक-एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रदर्शित करने के लिए साक्षात्कारपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैंकल्टी मेंबर, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरव्यू सेशन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैंकल्टी मेंबरों के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट्स के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ-साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

एलोक्यूशन सेशन: इच्छित डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व-मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299
interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्ट्रर करने के लिए **QR dksM** स्कैन करें

16. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment)

16.1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

दिव्यांगता समावेशन	- सुगम्य भारत अभियान: समावेशिता और सुगम्यता के बेमिसाल 9 साल पूरे हुए। - दिव्यांगों के लिए बाधा रहित ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जहाँ सुगम्यता मौलिक अधिकार हो। - सुगम्यता और सूचना: - दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। - सूचना को सुलभ बनाना: नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कानूनी राहों सहित लगभग 10,000 पन्नों के दस्तावेजों को दृश्यता के लिहाज से दिव्यांग जनों के लिए सुलभ बनाना है।
कौशल विकास एवं रोजगार	- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम शुरू किया गया। - रोजगार के अवसरों के लिए सहयोग: गारंटीकृत प्लेसमेंट और न्यूनतम मजदूरी के नियमों के अनुपालन के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। - बधिर समुदाय के लिए कौशल: YUNIQUE के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य बधिर समुदाय को निशुल्क और सुलभ कौशल प्रदान करना है, जिससे उनके करियर में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। - पर्पल टॉक्स: दिव्यांगजनों के लिए नवीन तकनीकों का विकास करने वाले स्टार्ट-अप और संगठनों के साथ वार्ता के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पहुंच का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और CRCs के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समावेशिता और जागरूकता	केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांग जनों के लिए पदों की पहचान और उनके आरक्षण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए।

16.2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice & Empowerment)

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु पहलें	- प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं। - युवा अचीवर्स हेतु उच्चतर शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस/SHREYAS) - एससी: इसमें चार उप-योजनाएं शामिल हैं:- - अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना: यह योजना केंद्रीय नोडल एजेंसी डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (DAF) द्वारा पैनल में शामिल 19 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE) के माध्यम से संचालित की जाती है। - अनुसूचित जातियों के लिए सर्वोच्च स्तर की शिक्षा। - अनुसूचित जातियों के लिए विदेश में शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। - अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। - लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ/SHRESTHA): अनुदान-सहायता प्राप्त संस्थानों (गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना आदि। - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY): इसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना है। - अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC)। - अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन: अनुसूचित जाति के छात्रों, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर और अटल इनक्यूबेशन सेंटर के साथ काम करने वालों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना। - कानूनी संरक्षण: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - समर्पित संस्थान: - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)।
------------------------------------	---

	> ई-शिकायत प्रबंधन पोर्टल (e-GMP): यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत NCSC द्वारा शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ शिकायत निवारण का 24x7 प्लेटफॉर्म है।
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पहले	• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त जनजातियों (DNT) के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पीएम-यशस्वी और श्रेयस नामक दो अम्ब्रेला योजनाएं शुरू की गई हैं जबकि DNT के लिए एक अलग योजना है। • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)। ○ पीएम-सूरज पोर्टल: इसका उद्देश्य सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत आर्थिक सशक्तिकरण पहलों को समेकित और सुव्यवस्थित करना है। • पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका संवर्धन कार्यक्रम (टूलिप/TULIP): यह कार्यक्रम हमारे कारीगरों के उत्पादों के विपणन और प्रचार-प्रसार के लिए है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा मिले, कारीगरों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि हो और उनके उत्पादों की बाजार में पहुंच बढ़े। • प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष/PM-DAKSH) योजना: यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास प्रदान करती है। • पिछड़ा वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-BC)। • विश्वास (VISVAS): विश्वास योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक पहल है। यह हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों (जिसमें हाथ से मैला ढोने वाले और कचरा बीनने वाले शामिल हैं) के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत आय-उत्पादक गतिविधियों हेतु ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है। ○ यह 2024-25 से 2025-26 तक चलेगी, जो मुद्रा (MUDRA), एनआरएलएम (NRLM) और सिडबी के प्रयास जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ समन्वय का लाभ उठाएगी।
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण	• विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन ○ मौजूदा कार्यक्रमों और पात्रता शर्तों में खामियों की पहचान करने के बाद इसका गठन डीएनटी समुदायों के लिए आवश्यक कल्याण और विकास कार्यक्रमों को तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, और उनकी समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया। • DNTs के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (SEED)
सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए पहले	• नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/NAMASTE): ○ यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। ○ इस योजना में शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों को स्थायी आजीविका प्रदान करके उनकी सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना की गई है। ○ सीवर सेप्टिक टैंक कर्मचारियों के साथ-साथ कचरा बीनने वालों को भी अतिरिक्त लक्ष्य समूह के रूप में शामिल किया गया है। ○ मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS) घटक। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)।
सामाजिक सुरक्षा के तहत उठाए गए कदम	• अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) ○ यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष पांच आवश्यकताओं; आश्रय, वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय संपर्क/सम्मानपूर्ण जीवन का ध्यान रखती है। • नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहल: आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल/ SMILE) योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास करना है। इसका उद्देश्य भिक्षुओं को समाज की मुख्यधारा में वापस लाकर 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' बनाना है। • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास: 'स्माइल' योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ○ बेसहारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 6 नए 'गरिमा गृह' आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। ○ राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 19 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (TWB) स्थापित किए गए हैं।

	- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान - राष्ट्रीय ड्रग दुर्व्यवहार निवारण केन्द्र (NCDAP) - NISD का ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति (T&B) प्रभाग।
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन	- डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना। - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार योजना: यह योजना माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं (10 वीं) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करती है। - डॉ. अम्बेडकर सामाजिक एकीकरण योजना: इस योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। - अत्याचार पीड़ितों को राहत देने के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति योजना। - डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (DAIC), नई दिल्ली: इस केंद्र को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीतिगत जानकारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। - डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (DANM): यह स्मारक दिल्ली में स्थित है और यह बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है।

**1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स**
प्रीलिम्स 2025 के लिए मात्र 60 घंटे में

ENGLISH MEDIUM
9 JAN, 5 PM

हिन्दी माध्यम
17 JAN, 5 PM

- 📖 संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- 📖 अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- 📖 प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- 📖 लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

17. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

ग्रीन स्टील मिशन	- स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन को घटाने और नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगति करने में मदद करना। - मिशन में ग्रीन स्टील के लिए PLI योजना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सरकारी एजेंसियों को ग्रीन स्टील खरीदने के अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं। - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्टील क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एकीकृत करना, और इस क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन करना है। ग्रीन स्टील के लिए टेक्सोनोमी : कम उत्सर्जन वाले स्टील को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करना, स्टील उद्योग के ग्रीन ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाना।
स्पेशलिटी स्टील-उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना	इसका उद्देश्य पूंजी निवेश को आकर्षित करना और आयात को कम करना है।
क्षमता विस्तार	- इस्पात विनियमन-मुक्त क्षेत्र है। - देश के सभी राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्टील क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीति का निर्माण करना। - सरकारी खरीद हेतु 'मेक इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से उत्पादित लौह और इस्पात उत्पाद (DMI&SP) नीति का कार्यान्वयन। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS) 2.0 का नवीनीकरण: घरेलू इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए आयातों की अधिक प्रभावी निगरानी करना।
कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना	स्टील क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs) मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक जैसे अलग-अलग देशों से कोकिंग कोयला खरीद रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रणनीति	भारत की स्टील ग्लोबल आउटलुक स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें सहयोग के चार रणनीतिक क्षेत्रों; कच्चा माल, निवेश, प्रौद्योगिकी और इस्पात निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस्पात की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से इस्पात की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। TCQCO पोर्टल, जिसके माध्यम से आयातित इस्पात खेपों के उपयोग की जांच की जाती है, अब इसे SIMS 2.0 पोर्टल के साथ मिला दिया गया है। फिर इसे स्विफ्ट 2.0 पहल के तहत कस्टम के ICEGATE के साथ एकीकृत किया जाएगा।

मासिक

समसामयिकी रिवीजन

कक्षाएं 2025

GS प्रीलिम्स और मेन्स

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

हिन्दी माध्यम

31 JAN | 5 PM

English Medium

25 JAN | 5 PM

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

► **Live/Online Classes** are available

18. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

18.1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances)

शिकायत निवारण	- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS): लंदन में राष्ट्रमंडल देशों की कैबिनेट बैठक में CPGRAMS को "अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली" तथा शिकायत निवारण के लिए वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी गई। - शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023: 89 में से 85 मंत्रालयों और विभागों ने GRAI 2022 की तुलना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर बेहतर समाधान दर का प्रदर्शन किया है। - सेवोत्तम (SEVOTTAM) योजना के तहत, 20 हजार राज्य शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 22 राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
राज्यों और RTS आयोगों के साथ सहयोग	- DARPG का सहयोग - DARPG ने जिला सुशासन सूचकांक 2023 के प्रकाशन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग किया है। - JK-IGRAMS शिकायत पोर्टल के नवीनीकरण हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ सहयोग किया, जिसका शुभारंभ जेके-समाधान (JK-SAMADHAN) के रूप में किया गया।
ई-ऑफिस	नवंबर 2024 तक कुल फाइलों में से ई-फाइलों के निर्माण की प्रक्रिया में ई-ऑफिस को 90.6 प्रतिशत तक अपनाया गया।
राज्यों के साथ सहयोगात्मक पहल योजना	यह सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है। ये परियोजनाएं ई-ऑफिस समाधान, प्रशासनिक सुधार, डोरस्टेप सेवाएं तथा मुकदमेबाजी प्रबंधन पर केन्द्रित हैं।
वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार	राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, DARPG को वर्ष 2023-24 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार)" से सम्मानित किया गया।

18.2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Department of Pension & Pensioners' Welfare (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)}

पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण	- शिकायतों के निपटारे में लगने वाला औसत समय 36 दिन (2018) से घटकर 26 दिन (2024) हो गया है। - केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) पोर्टल: इसमें शिकायतों को उनके स्रोत (ऑनलाइन, डाक या कॉल सेंटर) के आधार पर ट्रैक करना और उनके समाधान के लिए औसत निपटान समय-सीमा शामिल है।
उपदान में सुधार	उपदान सीमा बढ़ाना: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम उपदान सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है।
अन्य प्रमुख पहलें	- राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना - सेवानिवृत्त होने वाले 15 अधिकारियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशंसा-पत्र दिए गए। - रक्षा पेंशनभोगियों के लिए CGDA के साथ समन्वय - रक्षा पेंशनभोगियों के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) के साथ सक्रिय सहयोग।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
 ✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2025: **19 JANUARY**
 हिन्दी माध्यम 2025: **19 जनवरी**

19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare)

आयुष्मान भारत	- चार घटक और उपलब्धियां - आयुष्मान आरोग्य मंदिर: 1,75,338 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) चालू हो चुके हैं। - प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना - वर्तमान में, 12.37 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। - लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। - कुल बनाए गए आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% कार्ड महिलाओं के हैं। - आयुष्मान वय वंदना कार्ड: 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। 'आयुष्मान ऐप' को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें लाभार्थियों के लिए स्व-सत्यापन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। - प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा संक्रामक रोगों की निगरानी और किसी महामारी के एकदम से उभर आने पर प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना। - ICMR की आई-ड्रोन पहल ने कोविड टीके, सैंपल, दवाएं और ब्लड बैग की डिलीवरी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले गए: 71.52 करोड़ - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवर: 5,42,132
टीकाकरण- यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म	यू-विन (यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम-विन/ WIN) को टीकाकरण अभियान की दक्षता में सुधार लाने हेतु राष्ट्रव्यापी उपयोग के लिए लॉन्च किया गया।
क्षय रोग (टीबी) के लिए पहल	- राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP): क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। - पिछले 9 वर्षों में, 2014 से 2023 तक, टीबी के मामलों की समग्र अधिसूचना में 64% का सुधार हुआ है। - नई एंटी-टीबी दवाओं की शुरुआत – बेडाक्विलिन, डेलामानिड - ये दवाएं मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी के रोगियों को दी जाती हैं, जिनमें फ्लोरोक्विनोलोन के प्रति प्रतिरोधकता हो या न हो। - निक्षय पोषण योजना: उपचार की पूरी अवधि के लिए DBT के माध्यम से टीबी के रोगियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। - निक्षय मित्र पहल: इसका उद्देश्य टीबी के रोगियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है ताकि उपचार के परिणामों में सुधार हो सके। साथ ही सामुदायिक भागीदारी बढ़े और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का लाभ उठाया जा सके। - वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार - भारत में टीबी होने की दर 2015 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 195 तक हो गई, जो 17.7% की गिरावट को दर्शाती है।
राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम (चरण-V): 2023-26	- यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। 2024 में, देश में उच्च जोखिम और 'ब्रिज जनसंख्या' समूहों के एक करोड़ से अधिक लोगों को रोकथाम सेवाएं प्रदान की गई हैं।
मातृ स्वास्थ्य	मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

	- वर्तमान में भारत का MMR 97/लाख जीवित जन्म है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन/SUMAN): इसके तहत बिना किसी लागत के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। मातृ प्रसवकालीन शिशु मृत्यु निगरानी एवं प्रतिक्रिया (MPCDSR) सॉफ्टवेयर: सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश MPCDSR पोर्टल का उपयोग करके मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग और समीक्षा कर रहे हैं। प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को एक निश्चित दिन पर, निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्य/LaQshya (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव): यह पहल लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करती है। जननी सुरक्षा योजना (JSY): JSY राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है।
बाल स्वास्थ्य	- वर्ष 2020 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32 है। मुस्कान/MusQan- बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार पहल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): RBSK कार्यक्रम के तहत प्रसव केन्द्रों पर 38.23 लाख नवजात शिशुओं की जांच की गई है।
पोषण	- स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (MAA) अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है। एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम: 6-59 महीने के आयु वर्ग के 4.7 करोड़ बच्चों को हर महीने आयरन फोलिक एसिड (IFA) सिरप की 8-10 खुराकें दी गईं।
किशोर स्वास्थ्य	साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (WIFS) कार्यक्रम। किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना: 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। - स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
परिवार नियोजन	NFHS-5 (2019-21) की मुख्य विशेषताएं: - कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS 3 (2005-06) में 2.7 से घटकर NFHS 5 (2019-21) में 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.1 या उससे कम प्रतिस्थापन TFR हासिल किया है। - आधुनिक गर्भनिरोधकों के उपयोग की दर बढ़कर 56.5% हो गई है।
गर्भाश्वान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC एवं PNDT)	- PC एवं PNDT अधिनियम के तहत कुल 93,366 शव पंजीकृत किए गए हैं। - NFHS-5 (2019-21) ने राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में भी 10 अंकों का सुधार दर्ज किया है, जो NFHS-4 में 919 से बढ़कर 929 हो गया है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)	- FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है। कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन(CAC 47) का 47वां सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। - भारत के साबुत मिलेट अनाज के समूह मानक के नए कार्य-योजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम	- डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों में सुधार करने और दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भारत की G-20 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन - प्रबंधित ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लांच किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस/NIMHANS) को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया।

	• वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VoGSS): भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। जिसकी थीम थी "एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण"।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR)	• मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म: इस पहल का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा नवप्रवर्तकों को महत्वपूर्ण विकास चरणों के माध्यम से सहायता देना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचें और इस प्रक्रिया में उन्हें सशक्त बनाया जाए। • ICMR ने डेटा रिपॉजिटरी लॉन्च की है। यह उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट का एक केंद्रीकृत, सुरक्षित और सुलभ प्लेटफॉर्म है, जो डेटा की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। • उन्नति/UNNATI पहल (भारतीय बच्चों के पोषण, वृद्धि और विकास मूल्यांकन के मानदंडों को बेहतर बनाना): इसका उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के मौजूदा मानदंडों की सीमाओं के अनुरूप बच्चों के लिए भारत-विशिष्ट वृद्धि व विकास मानकों को स्थापित करना है। • ICMR - रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इकोसिस्टम (आई-राइज़) नीति का शुभारंभ: अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच को सभी के लिए सुलभ बनाता है। • डेंगीऑल के डेंगू वैक्सीन परीक्षण का शुभारंभ किया गया।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र	• मलेरिया ○ WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट (WMR) 2024 के अनुसार, वर्ष 2023 में वैश्विक मलेरिया के मामलों में देश का योगदान केवल 0.8% रहा तथा मलेरिया से संबंधित मृत्यु के 0.6% मामले दर्ज किए गए। ○ भारत ने 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। • कालाज़ार ○ सरकार ने ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से अधिक कालाज़ार मामले की रिपोर्टिंग करने वाले स्थानिक ब्लॉक्स की संख्या 'शून्य' कर ली है। • लिम्फेटिक (लसीका) फाइलेरिया (LF) ○ LF एक प्राथमिकता वाला उष्णकटिबंधीय रोग है जिसे भारत सरकार ने 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पहले समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। • जापानी इंसेफेलाइटिस ○ 355 जिलों में से 334 जिले नियमित टीकाकरण (RI) के अंतर्गत आ चुके हैं।
विविध	• भारत सरकार ने 2024 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। • राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन: इसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल रोग (SCD) को समाप्त करना है। • राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा-ई-संजीवनी डॉक्टर-से-डॉक्टर परामर्श और रोगी-से-डॉक्टर परामर्श की सुविधा प्रदान करके देश भर में विशेष चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। • राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली मानस/MANAS)। ○ टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है। • संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा: ○ राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) ○ "एक्यूंपंकचर पेशेवरों" को राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 की अनुसूची में शामिल किया गया है। • सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2024: 1 जून 2025 से प्रभावी होंगे।

- नए नियमों में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के दो सेट के प्रदर्शन को अनिवार्य किया गया है, जिन्हें प्रभावी तिथि से पहले और दूसरे बारह महीने की अवधि में लागू किया जाएगा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **तंबाकू नियंत्रण कानून 2024** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तकों हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **भारतीय राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम** एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य भारत में विपणन किये जाने वाले चिकित्सा उत्पादों के उपयोग से रिपोर्ट की गई प्रतिकूल घटनाओं को एकत्रित करना, उनका मिलान करना और उनका विश्लेषण करना है।
- **राज्यों की औषधि नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना (SSDRS):** SSDRS देश में राज्यों की औषधि नियामक प्रणाली और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने व उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है।

CSAT

क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025

(इसका उद्देश्य मूलभूत अवधारणाओं को रिवाइज करना और उन्हें सुदृढ़ करना, समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर बनाना, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समझ कौशल में सुधार करना है।)

प्रारंभ

English Medium

हिन्दी माध्यम

21 January, 1 PM

30 January, 1 PM

(Offline/Online)



20. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

प्रमुख उपलब्धियां	- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम - आवेदकों, SCAs और NMDFC के बीच ऋण लेखांकन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मिलान/ MILAN (NMDFC के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर) ऐप लॉन्च किया गया। - तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया।
जियो पारसी योजना	उद्देश्य: वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप के जरिए पारसी समुदाय की जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना।
वक्फ	अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया और इसे संसद की संयुक्त समिति (JPC) को भेज दिया गया है।

LIVE/ONLINE
Classes Available

www.visionias.in



Foundation Course GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: | 10 JAN, 9 AM | 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 21 जनवरी, 11 AM | 6 जनवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN

BENGALURU: 18 FEB

BHOPAL: 5 DEC

HYDERABAD: 9 DEC

JAIPUR: 20 JAN

JODHPUR: 3 DEC

LUCKNOW: 11 FEB

PUNE: 20 JAN

ADMISSION OPEN

CHANDIGARH

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 21 जनवरी, 11 AM | 6 जनवरी, 11 AM

JAIPUR: 20 जनवरी

JODHPUR: 3 दिसंबर

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/channel/UCVnIA5delhi)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.instagram.com/visioniasdelhi)

[/t.me/s/VisionIAS_UPSC](https://t.me/s/VisionIAS_UPSC)

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)





MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK



RECEPTION AREA



COUNSELING/MENTORING



FIRE EXIT PLAN



CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज— मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)— एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज— दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas— Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम — UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर—एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- **दक्ष (Daksha):** आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- **लक्ष्य (Lakshya):** मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)— सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग—अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT 365**
- **Mains 365**

स्टडी मैटेरियल— सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT 365** एवं **Mains 365**
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell — देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन



ASHOK DUBEY SIR



MRITYUNJAY SIR



RAJEEV RANJAN SIR



SUNIL KUMAR SINGH SIR

= हिंदी माध्यम टॉपर =



Aditya Srivastava



मोहन लाल



अर्पित कुमार



Shubham Kumar

UPSC CSE 2020



Bajarang Prasad

UPSC CSE 2022



Vikas Gupta

UPSC CSE 2022



Jatin Parashar

UPSC CSE 2022



DELHI

HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor,
Near Gate-6 Karol Bagh
Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



ENQUIRY@VISIONIAS.IN



/VISION_IAS



/C/VISIONIASDELHI



VISION_IAS



/VISIONIAS_UPSC



AHMEDABAD



BENGALURU



BHOPAL



CHANDIGARH



DELHI



JAIPUR



JODHPUR



GUWAHATI



HYDERABAD



LUCKNOW



PRAYAGRAJ



PUNE



RANCHI

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates



Aditya Srivastava

79

in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**



Animesh Pradhan



Ruhani



Srishti Dabas



Anmol Rathore



Nausheen



Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =



मोहन लाल



अर्पित कुमार



विपिन दुबे



मनीषा धार्वे

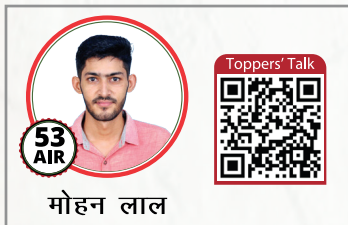


मयंक दुबे



देवेश पाराशर

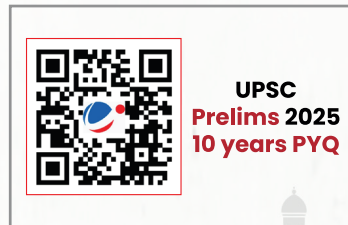
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें



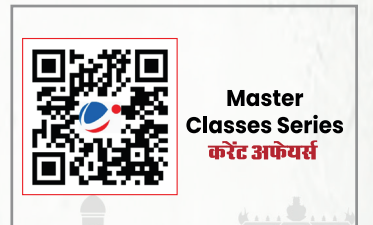
मोहन लाल



**UPSC
CSE 2026
सामान्य अध्ययन**



**UPSC
Prelims 2025
10 years PYQ**



**Master
Classes Series
करंट अफेयर्स**



DELHI

HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor,
Near Gate-6 Karol Bagh
Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



[@visioniashindi](https://www.youtube.com/@visioniashindi)



[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)



[/vision_ias_hindi/](https://www.instagram.com/vision_ias_hindi/)



[/hindi_visionias](https://www.telegram.com/hindi_visionias)



अहमदाबाद

बेंगलुरु

भोपाल

चंडीगढ़

दिल्ली

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

जोधपुर

लखनऊ

प्रयागराज

पुणे

रांची